राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र संख्या- 23 /2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक:लखनऊ:जुलाई 14 ,2025

विषयः अन्तर्राज्यीय गिरफ्तारी/ दबिश एवं विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा प्रोटोकाल का अनुपालन करने के सम्बन्ध में दिशा- निर्देश।

प्रिय महोदय/ महोदया,

कृपया अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अर्ध शा0 पत्र संख्याः डीजी-सात-एस-14(5)/2020, दिनांक 14 अगस्त 2020 (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विभिन्न अपराधों में वांछित अभियुक्तों की अन्तर्राज्यीय गिरफ्तारी के समय माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन (क्रि0) संख्याः 2179/2018 संदीप कुमार बनाम Govt. of NCT of Delhi व अन्य में पारित निर्णय के प्रस्तर 15 व 16 में अंकित सभी बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस मुख्यालय द्वारा उक्त सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने के उपरान्त भी कतिपय कमिश्नरेट/जनपदों के विवेचको द्वारा विवेचना निष्पादन सम्बन्धी कार्यों अथवा वांछित अभियुक्तों की तलाश / गिरफ्तारी हेतु राज्य के बाहर जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमति के सम्बन्ध में निर्दिष्ट प्रोटोकाल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, यह स्थिति कदापि उचित नहीं है।

3. उपरोक्त क्रम में विवेचकों द्वारा विवेचना निष्पादन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी / दबिश हेतु गैर राज्यों में जाने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा निर्धारित प्रोटोकॉल पालन करने हेतु पुनः निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये जा रहे हैः-

1. पुलिस अधिकारी को, जिसे मामले का दायित्व सौप दिया गया है, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से बाहर जाने के लिए लिखित रूप में या फोन पर (आग्रह के मामले में) उच्चतर / वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति / मंजूरी लेनी चाहिए।
2. ऐसे मामले में जब पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी करने का निर्णय लिया गया है तो उसे संतुष्टि के तथ्यों और कारणों को लेखबद्ध करना चाहिए जिससे संतुष्टि का पता चल सके कि विवेचना के उद्देश्य से गिरफ्तारी आवश्यक है। प्रथम दृष्टया उन्हे स्थानीय अधिकारिता न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 78 और 79 सीआरपीसी/ 80, 81 BNSS के तहत गिरफ्तारी / तलाशी वारण्ट का प्रयास करना चाहिए जिसमें अत्यावश्यक मामलों को छोड़कर जिसमें अभियुक्तों के भागने या साक्ष्य मिटाने या गिरफ्तारी / तलाशी वारण्ट प्राप्त करने में लगने वाला समय इस उद्देश्य को विफल कर देगा, पुलिस को ऐसे कारणों को दर्ज करना चाहिए जो किसी गिरफ्तारी / तलाशी वारण्ट के बिना दूसरे राज्य की यात्रा के लिए अति-आवश्यक कारण है।
3. राज्य के बाहर जाने से पहले पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पुलिस थाना की जनरल डायरी में विस्तार से प्रवृष्टि की जानी चाहिए।
4. यदि सम्भावित गिरफ्तार किये जाने वाला व्यक्ति महिला है तो एक महिला पुलिस अधिकारी को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। पुलिस अधिकारियों को अपना पहचान पत्र अपने साथ ले जाना चाहिए। टीम के सभी पुलिस अधिकारी वर्दी में होने चाहिए उनके पदनाम के साथ दृश्यमान और स्पष्ट पहचान की नाम पट्टिका धारण किया जाना चाहिए।

5. अन्य राज्य का दौरा करने से पहले पुलिस अधिकारी को स्थानीय पुलिस थाना से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह विवेचना की जानी है। गंतव्य तक पहुंचने के बाद सबसे पहले उसे सहायता और सहयोग की तलाश के लिए अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए। सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को यात्रा करने वाली टीम को सभी कानूनी सहायता प्रदान करना चाहिए। स्थानीय अधिकारिता के थाने में ऐसी समस्त प्रविष्टि को अंकित किया जाये।

6. जाँच के स्थान पर पहुँचने के बाद तलाशी की प्रक्रिया धारा 100 सीआरपीसी/ 103 BNSS की निर्धारित प्रक्रिया का पालन अक्षरशः किया जाना चाहिए। पड़ोस से स्वतन्त्र, सार्वजनिक गवाहों में शामिल होने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। गिरफ्तारी के मामले में पुलिस अधिकारी को अन्तर्गत धारा 41ए और 41बी और धारा 50 एवं 51 सीआरपीसी (35, 36,47,49 **BNSS**) की प्रक्रिया का पालन करना होगा। डी०के० वसु मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों और सीआरपीसी (**BNSS**) के प्राविधानों के अनुसार पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जानी चाहिए।

7. वापसी के समय पुलिस अधिकारी को स्थानीय पुलिस थाने की जनरल डायरी में गिरफ्तार व्यक्ति जिसे अपने राज्य में लाना है उसका स्पष्ट नाम और यदि कोई उससे वस्तु बरामद की गयी हो, का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

8. गिरफ्तार व्यक्ति के ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिये। यदि परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो तो 24 घण्टे में धारा 56 व 57 द०प्र०सं० (57 व 58 **BNSS**) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अभियोग के अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाना चाहिए।

9. पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी को समय, गिरफ्तारी स्थल पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों का विवरण तैयार किया जायेगा व गिरफ्तारी मैमो, गिरफ्तारी का समय, गिरफ्तार व्यक्ति के सगे सम्बन्धियों/ मित्रों को दी जाने वाली गिरफ्तारी सम्बन्धी सूचना का विवरण, कारण गिरफ्तारी का उल्लेख किया जायेगा।

4. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक- 12.12.2021 में दिये गये निर्देशों तथा उपर्युक्त बिन्दुओं का अपने निकट पर्यवेक्षण में अक्षरशः कडाई से सम्यक अनुपालन सुनिश्चित कराये तथा उक्त प्रयोजन हेतु गैर राज्य जाने हेतु नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पुलिस टीम को प्रस्थान कराया जाये। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता / लापरवाही न की जाए।

भवदीय

(राजीव कृष्णा) 14/7.

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।
संलग्नकः यथोपरि।

प्रतिलिपि- निम्नांकित अधिकारियों को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-पुलिस महानिदेशक, सी0आई0डी0/ई0ओ0डब्लू0, उ0प्र0 लखनऊ।
2-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज/अपराध/ एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ। 16.7.25
4-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5-पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0/ ए0एन0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।

संलग्नकः यथोपरि।

C.O.W., C.I.D.

अर्द्ध शा0 पत्र –डीजी–सात–एस–14(5)/2020

डा0 के0एस0प्रताप कुमार
आई0पी0एस0

अपर पुलिस महानिदेशक,अपराध
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः अगस्त 14 ,2020

विषयः–वांछित अभियुक्तों की अन्तर्राज्यीय गिरफ्तारी के समय मा0 उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन (कि0) संख्याः–2179/2018 संदीप कुमार बनाम Govt. of NCT of Delhi व अन्य में पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया रिट पिटीशन(कि0)संख्या–2179/2018, संदीप कुमार बनाम Govt. of NCT of Delhi व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एक दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया। गठित की गयी समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दिनांकित 04.02.2019 प्रस्तुत की, जिसमें राज्य की पुलिस द्वारा किसी अन्य राज्य में गिरफ्तारी किये जाने के समय पालन किये जाने वाले प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में विस्तृत सुझाव दिये गये हैं।

मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा समिति के इन सुझावों को अपने निर्णय के प्रस्तर–15 में अंकित करते हुये न्यायालय के निर्णय के प्रस्तर–15 तथा 16 के अनुसार अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये, जो संलग्न है।

अतः आप मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अपने निर्णय में पारित उपरोक्तांकित सभी बिन्दुओं पर संवेदनशील होकर जनपद में एक कार्यशाला आयोजित कर जनपद के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें।

उपरोक्त बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(डा0 के0एस0प्रताप कुमार)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, ईओडब्लू उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी उ0प्र0।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस/एसटीएफ, उ0प्र0।

वांछित अभियुक्तों की अन्तर्राज्यीय गिरफ्तारी के समय मा0 उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन (कि0) संख्याः—2179/2018 संदीप कुमार बनाम Govt. of NCT of Delhi व अन्य में पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

न्यायिक निर्णय के अंश प्रस्तर 15 व 16 निम्नवत् हैं।

The Committee has, after examining all of the above material in detail, given detailed suggestions as to the protocol to be followed by the police in the event of inter-state arrest. These read as under:

"1. The Police Officer after assignment of the case to him, must seek prior permission/sanction of the higher/superior officers in writing or on phone (in case of urgency) to go out of State/UT to carry out investigation.

2. In a case when the police officer decides to effect an arrest, he must set out the facts and record reasons in writing disclosing the satisfaction that arrest is necessary for the purpose of investigation. At first instance, he should move the Jurisdictional Magistrate to seek arrest/search warrants under Section 78 and 79 Cr PC except in emergent cases when the time taken is likely to result in escape of the accused or disappearance of incriminating evidence or the procurement of arrest/search warrant would defeat the purpose. The Police Officer must record reasons as to what were the compelling reasons to visit other State without getting arrest/search warrants.

3. Before proceeding outside the State, the police officer must make a comprehensive departure entry in the Daily Diary of his Police Station. It should contain names of the police officials and private individuals accompanying him; vehicle number; purpose of visit; specific place(s) to be visited; time and date of departure.

4. If the possible arrestee is a female, a lady police officer be made part of the team. The Police Officers should take their identity cards with them. All police officers in the team should be in uniform; bear accurate, visible and clear identification and name tags with their designations.

5. Before visiting the other State, the Police Officer must endeavour to establish contact with the local Police Station in whose jurisdiction he is to conduct the investigation. He must carry with him the translated copies of the Complaint/FIR and other documents in the language of the State which he intends to visit.

6. After reaching the destination, first of all, he should inform the concerned police station of the purpose of his visit to seek assistance and co-operation. The concerned SHO should provide/render all legal assistance to him. Entry to this effect must be made at the said police station.

7. After reaching the spot of investigation, search, if any should be strictly conducted in compliance of the procedure laid down u/s 100 Cr PC. All endeavour should be made to join independent public witnesses from the neighbourhood. In case of arrest, the police officer must follow the procedure u/s 41A and 41B and Section 50 and 51 Cr PC. The process of arrest carried out by the police must be in compliance with the guidelines given in DK Basu case (Supra) and the provisions of CrPC.

8. The arrested person must be given an opportunity to consult his lawyer before he is taken out of State.

9. While returning, the police officer must visit the local police station and cause an entry made in the Daily Diary specifying the name and address of the person(s) being taken out of the State; articles if any, recovered. The victim's name be also indicated.
10. Endeavor should be made to obtain transit remand after producing the arrestee before the nearest Magistrate unless exigencies of the situation warrant otherwise and the person can be produced before the Magistrate having jurisdiction of the case without infringing the mandate of S. 56 and 57 of Cr.P.C. within 24 hours.
11. The magistrate before whom the arrestee is produced, must apply his mind to the facts of the case and should not grant transit remand mechanically. He must satisfy himself that there exists material in the form of entries in the case diary that justifies the prayer for transit remand. The act of directing remand of an accused is fundamentally a judicial decision. The magistrate does not act in executive capacity while ordering detention of the accused. He must ensure that requirements of S. 41 (l)(b) are satisfied. The police officer must send the case diary along with the remand report so that the magistrate can appreciate the factual scenario and apply his mind whether there is a warrant for police remand or justification for judicial remand or there is no need for any remand at all. The magistrate should briefly set out reasons for his decision.
(Manubhai Ratilal Patel v. State of Gujarat, (2013) 1 SCC 314)
12. Another mandatory procedural requirement for the Magistrate considering a transit remand application is spelt out in Article 22 (1) of Constitution of India. This entitles the person arrested to be informed as soon as may be the grounds of such arrest. The Magistrate has to ensure that the arrested person is not denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. The Magistrate should ask the person arrested brought before him whether in fact he has been informed of the grounds of arrest and whether he requires to consult and be defended by any legal practitioner of his choice. (DK Basu, Supra) After the pronouncement of this judgment by the Hon'ble Supreme Court, new Sections 41A to 41D have been added to prevent unnecessary arrest and misuse of powers. Denying a person of his liberty is a serious matter.
13. In terms of S. 41C, control rooms be established in every district. Names and addresses of the persons arrested and designation of the Police Officers who made the arrest be displayed. Control Room at State level must collect details of the persons so arrested.
14. The police officer must record all the proceedings conducted by him at the spot and prepare an 'arrest memo' indicating time, date of arrest and name of the relation/friend to whom intimation of arrest has been given. It must reveal the reasons for arrest.
15. Since the arrestee is to be taken out of his State to a place away where he may not have any acquaintance, he may be permitted to take along with him (if possible), his family member/acquaintance to remain with him till he is produced before the jurisdictional Magistrate. Such family member would be able to arrange legal assistance for him.

16. The arrested person must be produced before the jurisdictional Magistrate at the earliest, in any case, not beyond 24 hours from the date of arrest excluding the journey time so that arrest of such person and his detention, if necessary, may be justified by a judicial order. The 24 hours period prescribed u/s 57 Cr PC is the outermost limit beyond which a person cannot be detained in police custody. It does not empower a police officer to keep a person in police station a minute longer than is necessary for the purpose of investigation and it does not give him an absolute right to keep a person till 24 hours.
17. On arrival at the police station, the police officer must make an arrival entry in the record and indicate the investigation carried out by him, the person arrested and the articles recovered. He should also inform his senior police officers/SHO concerned about it immediately. The superior Police Officer shall personally supervise such investigation.
18. The police officer should effect arrest u/s 41(l)(b) Cr PC only when he has reasonable suspicion and credible information. He must satisfy himself about the existence of the material to effect arrest. There must be definite facts or averments as distinguished from vague surmises or personal feelings. The materials before him must be sufficient to cause a bona-fide belief. He cannot take shelter under another person's belief or judgment. He must affect arrest at his own risk and responsibility as the effect of illegal arrest could be commission of offence of wrongful confinement punishable u/s 342 IPC. Burden lies on the IO to satisfy the Court about his bona-fide. No arrest can be made because it is lawful for the police officer to do so. Denying a person of his liberty is a serious matter.
19. Medical examination soon after arrest to avoid possibility of physical torture during custody should be conducted.
20. The IO must maintain a complete and comprehensive case diary indicating the investigation carried out by him.
21. The log book of the vehicle used for transportation must be maintained and signed. The IO must indicate whether the vehicle was official or a private one; name of its driver and how and by whom it was arranged. Only official vehicle should be used for transportation to the extent possible.
22. At the time of recovery of the prosecutrix, the police officer, if he is satisfied that she is adult, should ascertain from her at the spot, whether she was present there with her free will. If the victim/prosecutrix is not willing to accompany the police officer or her relatives, the police officer must not exert force on the prosecutrix to take her away against her wishes. However, if the prosecutrix/victim of her own accord expresses willingness to accompany the police officer/relatives, her consent in writing should be obtained at the spot.
23. In case where the police officer finds the victim/prosecutrix to be a 'minor', soon after recovery, she should be produced before the local Child Welfare Committee for further decision regarding her custody. She must not be made to stay in the Police Station during night hours.
24. Statement of the prosecutrix u/s 164 Cr.P.C. must be recorded at the earliest.
25. MHA/Central Govt/Commissioner of Police must frame suitable guidelines for police officers to render all suitable assistance. The failure to adhere to the rules/guidelines should render the police officer liable for departmental action as well as contempt of the Court.